ग्रामीण पंजाब में अनुसूचित जातियों के बीच जल पहुँच संबंधी चुनौतियों का समाधान: परिप्रेक्ष्य, मुद्दे और समाधान

सरोज शर्मा, शोधार्थी, हिंदी, द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)

सारांश

जल मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है तथा स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल तक समान पहुँच प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधनों की उपलब्धता और वितरण सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। विशेष रूप से ग्रामीण पंजाब में अनुसूचित जातियों के समुदायों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, जल वितरण में असमानता, सामाजिक भेदभाव, आर्थिक विषमता तथा बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पंजाब में अनुसूचित जातियों के बीच जल पहुँच से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना तथा उनके सामाजिक, आर्थिक एवं संस्थागत कारणों का विश्लेषण करना है। पंजाब के ग्रामीण समाज में जातिगत संरचना और सामाजिक असमानता कई बार जल संसाधनों के समान उपयोग में बाधा उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त, पेयजल की गुणवत्ता, जल स्रोतों का रखरखाव, भूमिगत जल का प्रदूषण, जल आपूर्ति व्यवस्था की सीमाएँ तथा सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव भी इस समस्या को गंभीर बनाते हैं। इस अध्ययन में जल तक पहुँच के संदर्भ में सामाजिक न्याय, समानता, मानवाधिकार और ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। साथ ही, अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकारी नीतियों, स्थानीय प्रशासन, पंचायतों तथा सामुदायिक सहभागिता की भूमिका का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि जल संबंधी असमानताओं का समाधान केवल जल संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना, समान वितरण व्यवस्था विकसित करना, जल गुणवत्ता की नियमित जाँच करना तथा वंचित समुदायों की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। निष्कर्षतः, ग्रामीण पंजाब में अनुसूचित जातियों के लिए जल की समान एवं सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित करना सामाजिक न्याय, मानव गरिमा और समावेशी ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य शब्द: ग्रामीण पंजाब, अनुसूचित जातियाँ, जल पहुँच, पेयजल एवं स्वच्छता, सामाजिक असमानता, जातिगत भेदभाव, जल संसाधन प्रबंधन, सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास, सामुदायिक सहभागिता